

भास्कर खास

बिछेगा 2400 तालाबों का जाल, 29 करोड़ की सब्सिडी से मछली उत्पादन में नंबर-1 बनेगा बिहार बिहार में नीली क्रांति का महा-अभियान: बेकार पड़ी चौर की जमीन को तालाब बनाकर संवारेगी सरकार... इनमें 60 फीसदी उत्तर बिहार में होंगे

अमन कुमार सिंह | छपरा

बिहार अब मछली उत्पादन के क्षेत्र में इतिहास रचने जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में मछली उत्पादन को 8 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड लक्ष्य के पार ले जाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए हजारों एकड़ में फैली बेकार 'चौर' (जलजमाव वाली निचली जमीन) का कायाकल्प किया जाएगा। सात निश्चय पार्ट-2 के तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने इस साल पूरे बिहार में 'क्लस्टर आधारित' तालाब निर्माण का बड़ा लक्ष्य तय किया है।

इस साल राज्य भर में लगभग 600 हेक्टेयर भूमि को चिह्नित किया गया है। यहां निजी और क्लस्टर स्तर पर नए तालाब खोदे जाएंगे। इस हिसाब से राज्य में इस साल 1,200 से 2,400 नए तालाब खोदने का लक्ष्य है। योजना का 60% लक्ष्य उत्तर बिहार के चौर प्रधान जिलों के लिए है। इसमें पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

सब्सिडी का पिटारा: 29.65 करोड़ रुपए का बजट

इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए सरकार 29.65 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दे रही है।



70% सब्सिडी: अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए।

50% सब्सिडी: सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए।

40% : उद्यमियों के लिए। इच्छुक मत्स्य निदेशालय के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

भास्कर नॉलेज
ये हैं तालाब निर्माण के 3 स्वीकृत मॉडल

मॉडल 1: एक हेक्टेयर में 2 तालाब (इनपुट सहित) - लागत 8.88 लाख

मॉडल 2: एक हेक्टेयर में 4 तालाब (इनपुट सहित) - लागत 7.32 लाख

मॉडल 3: एक हेक्टेयर में 1 तालाब और व्यापक भूमि विकास - लागत 9.60 लाख



भास्कर इनसाइट

अब सब्सिडी डकारना मुमकिन नहीं, सैटेलाइट रखेगी नजर

पहले व्यक्तिगत तौर पर छोटे तालाबों के लिए अनुदान देना अव्यावहारिक था। अक्सर कागजों पर तालाब दिखाकर सब्सिडी डकारने के मामले आते थे। लेकिन अब पूरा फोकस 'क्लस्टर' (अधिकतम 20 हेक्टेयर) पर है। क्लस्टर में खेती होने से एक ही जगह कई सुविधाएं मिल जाती हैं, जिससे लागत घटती है। अब सैटेलाइट मैपिंग और जियो-टैगिंग के जरिए निगरानी हो रही है, जिससे भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगेगी।

यूपीएससी • भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय सहित कई विभागों में भर्तियों के लिए युवाओं को मौका

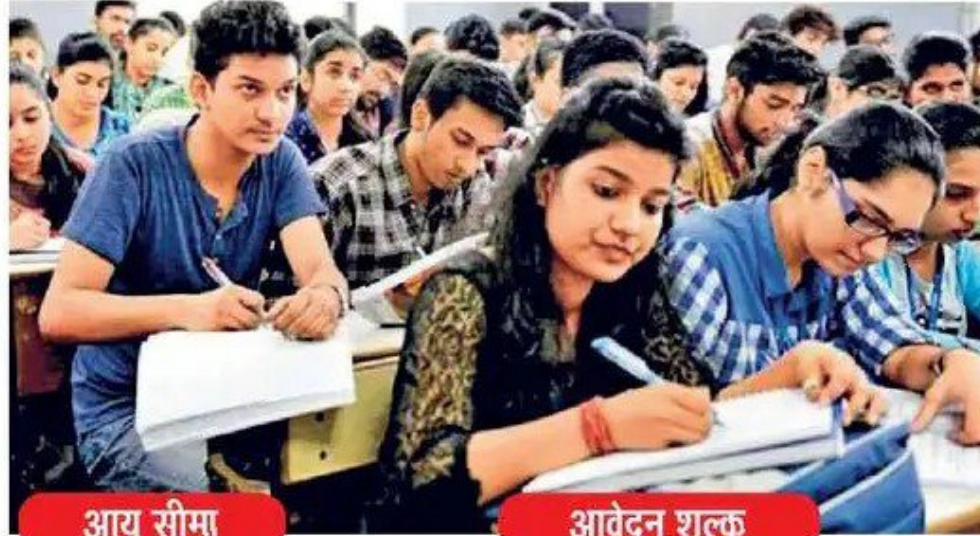
केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप A और ग्रुप B के 194 पदों के लिए आई वैकेंसी

UPSC ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप A और ग्रुप B के 194 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के माध्यम से DGCA, PESO, डाक विभाग, IMD, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय, MSME मंत्रालय सहित कई विभागों में भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार upsc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता

एसयूडीनेस ऑफिसर: फिजिक्स/मैथ/विमान रखरखाव में ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग + AME लाइसेंस, **डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव**: केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री / केमिस्ट्री में एमएससी।, **मैनेजर (मेल मोटर सर्विस)**: मैकेनिकल/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बी टेक, **जूनियर टेक्निकल ऑफिसर**: ऑथल टेक्नोलॉजी बीटेक/बीई या शूगर टेक पीजी डिप्लोमा, **जूनियर टेक्निकल ऑफिसर (केमिकल इंजीनियरिंग)**: केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर, **साइंटिफिक ऑफिसर**: फिजिक्स पीजी, मैकेनिकल, मेटलर्जी डिग्री, डिप्टी सुपरिटेंडिंग, **आर्कियोलॉजिकल इंजीनियर**: सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री, एसोसिएट प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग: बीई, बीटेक, एम

टेक, पीएचडी, लेक्चरर (परशियन लैंग्वेज): परशियन में पीजी, लेक्चरर (तिब्बेतन लैंग्वेज): तिब्बती भाषा में पीजी, **साइंटिस्ट वी (एटमॉस्फेरिक साइंस)**: संबंधित विषय में पीजी, **साइंटिस्ट वी (जनरल मीटिरियोलॉजी)**: संबंधित क्षेत्र में पीजी, **साइंटिस्ट वी (इंस्ट्रुमेंटेशन)**: इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री, **डिप्टी डायरेक्टर (सिविल इंजीनियरिंग)**: सिविल इंजीनियरिंग डिग्री, **पीजी, जॉइंट असिस्टेंट डायरेक्टर**: बीटेक, बीई, बीएससी, **असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर**: संबंधित क्षेत्र में बैचलर डिग्री डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस सेफ्टी: माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री, **असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड - 1 (IEDS) (Chemical)**: संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री



आयु सीमा

पद के अनुसार, अधिकतम 30 - 48 वर्ष है।

आवेदन शुल्क

जनरल, ओबीसी, इंडब्ल्यूएस (पुरुष) के लिए ₹25, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, महिला नि:शुल्क है।

चयन प्रक्रिया

रिटन एजाम, इंटरव्यू और मेडिकल एजाम के आधार पर होगा।



लास्ट डेट

12 जून
2026

कैसे करें आवेदन

ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर, मेल आईडी आदि दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें। डाक्यूमेंट्स अपलोड करें फीस देकर फॉर्म सबमिट कर दें।

संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा, 'पेपर लीक' की परिभाषा क्या है

ओएसएम से जुड़े मुद्दे पर सीबीएसई से भी किए तीखे सवाल

नई दिल्ली, प्रेस : संसद की एक समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उसकी परिभाषा में 'पेपर लीक' किसे माना जाएगा। यह भी पूछा है कि वर्ष 2018 से अब तक आयोजित परीक्षाओं में क्या किसी प्रश्नपत्र के लीक होने की घटना हुई? सूत्रों के अनुसार, समिति की प्रश्नावली पिछले सप्ताह उसके समक्ष एनटीए के अधिकारियों की पेशी के बाद आई है। अधिकारियों ने समिति को बताया था कि उनकी प्रणाली से कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। सिर्फ एक "गेस पेपर" के कुछ प्रश्न पहले से प्रसारित हुए थे, जिन्हें पेपर लीक के रूप में प्रस्तुत किया गया।

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय समिति नीट पेपर लीक मामले और सीबीएसई के आन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम मामले की जांच कर रही है। समिति ने एनटीए व सीबीएसई सहित शीर्ष अफसरों को तलब किया है। ओएसएम प्रणाली व नीट परीक्षा पर लिखित उत्तर मांगे हैं।

- ▶ पिछले सप्ताह समिति के समक्ष एनटीए अधिकारियों की पेशी के बाद सामने आई प्रश्नावली
- ▶ संसदीय समिति ने एनटीए से पूछा- 2018 से अब तक कितनी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए
- ▶ नीट-यूजी 2024 के प्रश्नपत्र में अनियमितताओं के आरोपों की कोई और जांच भी कराई थी



दिग्विजय सिंह। फाइल

सीबीएसई को आज तो एनटीए को 10 तक देना है लिखित जवाब

सीबीएसई को आज (आठ जून) और एनटीए को 10 जून तक समिति के सवालों का जवाब देना है। समिति ने सीबीएसई से ओएसएम सिस्टम के लिए जारी अलग-अलग रिक्वेस्ट फार प्रपोजल में कथित बदलावों के बारे में भी जानकारी मांगी है। यह भी पूछा है कि अनुबंध देने से पूर्व कोएम्प्ट की पृष्ठभूमि की कोई

जांच-पड़ताल की गई थी या नहीं। समिति ने यह भी जानना चाहा कि क्या उसे इसकी जानकारी थी कि कोएम्प्ट एड्युकेट या इसके निदेशक पहले ग्लोबरेना टेक्नोलॉजीज से जुड़े थे, जिसके मूल्यांकन साफ्टवेयर में 2019 के तेलंगाना इंटरमीडिएट परिणामों की जांच में खामियां पाई गई थीं।

समिति ने एनटीए से पूछा, क्या उसने सीबीएसई जांच के अलावा नीट-यूजी 2024 के प्रश्नपत्र में अनियमितताओं के आरोपों की कोई जांच कराई थी। एनटीए से गत तीन वर्षों के लिए उसके कर्मियों की संख्या, 2022 से की गई भर्तियों के बारे में भी पूछा। उच्च शिक्षा विभाग में पेश की गई वार्षिक रिपोर्ट की कापी भी

मांगी है। सूत्रों के अनुसार, इसमें राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट की 101 सिफारिशों में से प्रत्येक पर विस्तृत विवरण व एनटीए द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने जून 2024 में इसरो के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति

खराब रिकार्ड वाले बोलीदाताओं को अयोग्य ठहराने का प्रविधान क्यों हटाया?

समिति ने पूछा है कि ओएसएम अनुबंध के लिए जारी तीसरे आरएफपी में खराब प्रदर्शन का पिछला रिकार्ड रखने वाले बोलीदाताओं को अयोग्य ठहराने वाले प्रविधान को क्यों हटा दिया गया था। साथ ही यह सवाल भी किया गया कि तीसरे आरएफपी में पहले से काली सूची में डाले गए बोलीदाताओं को प्रतिबंधित करने वाले प्रविधान को केवल वर्तमान में काली सूची में डाले गए बोलीदाताओं को बाहर करने के लिए 'कमजोर' क्यों किया गया और बोलीदाता के लिए न्यूनतम कंपनी टर्नओवर विशेष रूप से 50 करोड़ रुपये क्यों निर्धारित किया गया। पैल ने यह भी पूछा कि सीबीएसई द्वारा आरएफपी में वांछित न्यूनतम स्कैनिंग रिजोल्यूशन 300 से घटाकर 200 डीपीआई क्यों किया गया।

को एनटीए के जरिये परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारु, निष्पक्ष संचालन के लिए सुझाव देने का दायित्व सौंपा था। एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार तथा डाटा सुरक्षा प्रोटोकाल को मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर सिफारिशें देने को कहा गया था।

(पेज-तीन और पांच भी देखें)

सीधी बात

नेपाली प्रधानमंत्री ने सीमा विवाद पर चीन और ब्रिटेन की भूमिका का किया था जिक्र, विदेश मंत्री शिशिर खनल ने कहा, भारत-नेपाल संबंधों को पुराने बोझ का बंधक नहीं बनाएंगे

सीमा विवाद सुलझाने में किसी की मध्यस्थता नहीं : नेपाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल ने रविवार को स्पष्ट कहा कि काठमांडू भारत के साथ सीमा विवाद को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना, मौजूदा द्विपक्षीय तंत्रों के जरिये सुलझाना चाहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब दोनों पक्ष खुले दिल, तर्कसंगत सोच और आपसी सम्मान के साथ बैठते हैं तो कोई समस्या इतनी बड़ी या जटिल नहीं होती।

नेपाल दूतावास की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ संबंधों पर खनल ने कहा, नेपाल नई दिल्ली को 21वीं सदी की भू-राजनीति के अतिसंवेदनशील चश्मे से नहीं देखना चाहता। दोनों देशों के बीच एक स्पष्ट व पारदर्शी एजेंडा होना चाहिए। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की नई सरकार को पूरी तरह नई राजनीतिक वास्तविकता बताते हुए खनल ने कहा, यह सरकार लेकर



नई दिल्ली में रविवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल। एएनआइ

भारत नेपाल संबंधों को पुराने बोझ का बंधक नहीं बनाना चाहती।

खनल की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई, जब नेपाल के प्रधानमंत्री शाह ने हाल ही में सीमा विवाद पर चीन और ब्रिटेन की भूमिका का जिक्र किया था, जिसे भारत ने साफ तौर पर खारिज कर दिया था। खनल ने स्पष्ट किया कि ब्रिटेन से संबंधित

विदेश मंत्री ने कहा, सीमा बाधा नहीं पुल का काम करती है

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल ने सीमा मुद्दे पर कहा कि सच्ची निर्भरता में सीमाएं बाधा नहीं, बल्कि पुल का काम करती हैं। हालांकि, खनल ने कलापानी-

लिपुलेख-लिम्पियाधुरा क्षेत्र पर नेपाल का दावा फिर से दोहराया और कहा कि काठमांडू इस मुद्दे को द्विपक्षीय तंत्र से ही हल करना चाहता है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा समझौते पर चिंता जताई

शिशिर खनल ने भारत-चीन के बीच लिपुलेख मार्ग पर कैलाश मानसरोवर यात्रा संबंधी समझौते पर नेपाल की चिंता भी व्यक्त की और कहा कि नेपाल की सहमति के बिना ऐसे फैसले नहीं हो सकते। उन्होंने 2026 को दोनों देशों के संबंधों को बदलने का सबसे अनुकूल समय बताया। खनल का कहना था कि नई सरकार का मुख्य लक्ष्य कागजी वादों और वास्तविकता के बीच की खाई को पाटना तथा टोस बदलाव वाले परिणाम देना है।

टिप्पणी केवल ऐतिहासिक दस्तावेज और ब्रिटिश लाइब्रेरी-म्यूजियम से जानकारी हासिल करने तक सीमित थी, न कि मध्यस्थता की मांग।

उन्होंने कहा-आइए ऐसी साझेदारी बनाएं जो अतीत की चिंताओं से बंधी न हो, बल्कि साझा भविष्य की ऊंची उम्मीदों और संभावनाओं से प्रेरित हो। खनल ने भारत

को तेजी से उभरती वैश्विक आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति बताते हुए कहा कि नेपाल इसके साथ अपनी आकांक्षाओं की ऊर्जा जोड़ना चाहता है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई विस्तृत वार्ता का जिक्र करते हुए कहा कि व्यापार, आधुनिक प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग तेजी से प्रगाढ़ किया जाएगा।

मोदी की अध्यक्षता में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सुधारों पर होगा मंथन

11 जून को होगी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक

राज्यों की आर्थिक प्रगति की रफ्तार कैसे बढ़े, इस पर भी होगा विमर्श
जागण खूरो, नई दिल्ली

देश में पेपर लीक की घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। यह बैठक 11 जून को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की होगी और इसमें शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए आवश्यक मानव संसाधन विकास, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, सैंकेंडरी स्तर की शिक्षा व्यवस्था, और बच्चों की एक्स्ट्रा कैरीकुलर गतिविधियों यानी खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और लीडरशिप कार्यक्रम आदि को लेकर किस तरह की नीति बनाई जाए, इस पर चर्चा होगी। साथ ही इस पर भी विमर्श होगा कि किस तरह से राज्यों में नियमों व व्यवस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा उदारवादी बनाकर आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज की जाए।

बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के भाग लेने की संभावना है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में



नरेन्द्र मोदी। फाइल

पेपर लीक से संबंधित मुद्दे सीधे तौर पर शामिल नहीं होंगे, लेकिन कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा इस विषय को उठाए जाने की संभावना है।

सभी राज्यों को पहले ही यह संदेश दिया गया है कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, ताकि मुख्यमंत्री अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकें। मुख्य रूप से, विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुसार मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और केंद्र तथा राज्यों के बीच सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कांग्रेस शासित राज्यों के नए मुख्यमंत्रियों जैसे कि केरल और कर्नाटक द्वारा पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकार को असहज करने का प्रयास किया जा सकता है।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के

बाद हो रही इस बैठक में बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्रु अधिकारी, केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ क्रियज पट्टली बार भाग ले सकते हैं।

सूत्रों का कहना है कि इस बैठक को मई, 2026 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ हुई अलग-अलग बैठकों के संदर्भ में भी देखना चाहिए। उक्त बैठकों में मोदी ने पश्चिम एशिया संकट (अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष) से उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए रिकॉम एक्सप्रेस और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों के स्तर पर कारोबार करने की राह की अड़चनों को दूर करने को प्राथमिकता के तौर पर लेने की बात कही थी। प्रधानमंत्री की मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक में कई ऐसे फैसले किए गए थे जिनको लेकर अब मुख्यमंत्रियों के साथ विमर्श किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि इसमें घामपंथी हिंसा से मुक्त कराये गए जिलों व क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करना भी शामिल है। बताया जा रहा है कि कुछ विषयों पर नीति आयोग की तरफ से तैयार किए गए प्रेजेंटेशन भी दिए जाने की संभावना है।

दिग्विजय सिंह की प्रधानमंत्री मोदी से त्रिभाषा नीति पर अमल रोकने की अपील

नई दिल्ली, प्रे: वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) द्वारा कक्षा नौ के छात्रों के लिए तीन भाषाओं को पढ़ाने की नीति के अनिवार्य कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की है और उनसे इसे रोकने की अपील की है। शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेलों पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस नीति का अचानक कार्यान्वयन, बिना पर्याप्त शिक्षकों, पाठ्यपुस्तकों या संक्रमण के समय के गंभीर व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, "जो कि सीबीएसई के आन-सूत्रन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली के जल्दबाजी में कार्यान्वयन के दौरान देखे गए अराजकता के समान है।"

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी को पत्र में लिखा है कि "मैं यहां एक प्रतिनिधित्व भेज रहा हूं जो सीबीएसई कक्षा नौ के छात्रों के चिंतित माता-पिता के एक समूह से प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान मध्य सत्र में तीन-भाषा नीति के अनिवार्य कार्यान्वयन का विरोध कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक

कांग्रेस नेता बोले-बिना पर्याप्त शिक्षकों, पाठ्यपुस्तकों के आएगी बाधा
कहा-मामला न्यायालय में है, कोर्ट का निर्णय 15 जुलाई को आना है



दिग्विजय सिंह। फाइल

अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने अभी तक भाषाओं की ग्रेडेड पाठ्यपुस्तकें जारी नहीं की हैं और इसलिए सीबीएसई ने एनसीईआरटी की कक्षा छह की पाठ्यपुस्तकों के उपयोग की सिफारिश की है।

सिंह ने तर्क किया कि यह स्थिति विशेष रूप से दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों

के छात्रों के लिए असहनीय है, जहां हिंदी नहीं बोली जाती और स्थानीय जनजातीय भाषाएं सीबीएसई की मान्यता प्राप्त भाषा सूची में नहीं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत कई स्कूलों के लिए एक लोकप्रिय तीसरी भाषा के विकल्प के रूप में उभरी है, लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि योग्य संस्कृत शिक्षकों और उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों की गंभीर कमी है, जो इस सुंदर भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य को विफल कर देगी।

सिंह ने अपने पत्र में लिखा, "मैं समझता हूं कि मामला न्यायालय में है, लेकिन माननीय न्यायालय का निर्णय केवल 15 जुलाई 2026 को आने वाला है। यह उस तिथि के बाद है जिस पर स्कूलों को तीसरी भाषा के शिक्षण का कार्यान्वयन करना है (यानी, एक जुलाई 2026)। इसलिए, मैं आशा करता हूं कि यह मामला आपके तालकालिक और सहानुभूतिपूर्ण विचार का विषय बनेगा, ताकि लाखों छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की सुरक्षा हो सके, जो सही और अच्छी तरह से तैयार की गई नीति निर्णयों पर निर्भर करते हैं।"

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्वदेशी न्यायशास्त्र पर दिया विशेष जोर

नई दिल्ली, प्रेस : भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने "स्वदेशी न्यायशास्त्र" के विकास पर विशेष जोर देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रौद्योगिकी को मानव तर्क के लिए सहायक के रूप में देखा है, न कि स्वतंत्र न्यायिक विचार के विकल्प के रूप में। उन्होंने कहा, युवा वकील, न्यायिक अधिकारी और कानूनी पेशेवर न्यायपालिका के तकनीकी परिवर्तन के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत हैं।

आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में "संविधानिक वादा से डिजिटल वास्तविकता: एआइ और तकनीकी उन्नति के युग में न्याय की सुरक्षा" विषय पर सीजेआइ ने यह भी कहा, तकनीक कभी भी मानव निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। चल रही प्रौद्योगिकी पहलों के अलावा, न्यायपालिका के लिए स्वदेशी एआइ पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। कहा, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने प्रौद्योगिकी को मानव तर्क के लिए सहायक के रूप में देखा है, न कि स्वतंत्र न्यायिक विचार के विकल्प के रूप में। प्रौद्योगिकी ने न्याय तक पहुंच



मुख्य न्यायाधीश
सूर्यकांत। फाइल

चीफ जस्टिस
बोले-युवाओं का
योगदान
न्यायपालिका के
तकनीकी परिवर्तन
के लिए
प्रेरणादायक

के संविधानिक वादे से परे कुछ योगदान दिया है। उन्होंने कहा, "भारत में कानून के क्षेत्र में युवा शब्द इतना अनुकूलनशील है, चाहे वह जिला अदालत का न्यायिक अधिकारी हो, चाहे सरकारी वकील और यहां तक कि जो कार्पोरेट संस्थाओं को कानूनी सलाहकार के रूप में मदद कर रहे हैं। सभी युवा मस्तिष्क इतने अनुकूलनशील हैं, इतनी तेजी से इसे अपनाते हैं, कि वे भारतीय न्यायपालिका के लिए इन सुधारात्मक परिवर्तनों को लाने के लिए वास्तव में प्रेरणादायक स्रोत बने हैं।" कहा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली विशाल मात्रा में कानूनी पाठ को आश्चर्यजनक गति से संसाधित कर सकती है।

अमेरिका-ईरान में फिर बढ़ रहा संघर्ष

अमेरिकी सेना ने दो ईरानी ड्रोन को मार गिराया, एक दिन पहले भी दोनों ने एक-दूसरे पर किए थे हमले

ईरानी संपत्ति से खाड़ी देशों के नुकसान की होगी भरपाई

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

अमेरिका और ईरान के बीच लागू नाजुक युद्धविराम पर खतरा बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि उनके बीच एक बार फिर संघर्ष बढ़ रहा है। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने होर्मुज स्ट्रेट में दो ईरानी ड्रोन को मार गिराया। जबकि एक दिन पहले भी दोनों ने एक-दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए थे।

एएनआइ के अनुसार, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकाम) ने शनिवार देर रात एक बयान में बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के दो हमलावर ड्रोन को मार गिराया, जो होर्मुज में कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा बन गए थे। सेंटकाम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आज सुबह पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना ने होर्मुज में अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय यातायात को खतरे में डालने वाले दो ईरानी हमलावर ड्रोन को मार गिराया।" एक दिन पहले भी दोनों ने एक-दूसरे पर हमले किए थे। ईरान ने शुक्रवार को होर्मुज और खाड़ी देशों की दिशा में ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए, जिन्हें अमेरिकी रक्षा प्रणालियों ने विफल कर दिया था। इसके जवाब में अमेरिका ने उसके रडार समेत निगरानी ठिकानों पर हमले किए। तेहरान ने इसे

▶ अमेरिका ने ईरान के रडार समेत निगरानी ठिकानों पर हमले किए

▶ तेहरान ने अमेरिका के हमले को युद्धविराम का उल्लंघन बताया



होर्मुज जलडमरूमध्य। फाइल



अराघची ने ट्रंप के दावे को किया खारिज

एएनआइ के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने देश के सुप्रीम लीडर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने ट्रंप को वास्तविक दुनिया में रहने की सलाह दी। उनका यह बयान ट्रंप के उस दावे के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भविष्य में ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई से मुलाकात हो सकती है।

युद्धविराम उल्लंघन बताया है। शनिवार देर रात ईरान के खार्ग द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गईं।

रायटर के मुताबिक, अमेरिका अब उन ईरानी संपत्तियों का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है, जिन्हें प्रतिबंधों के तहत जब्त किया गया था। इस राशि से

ईरान के हमलों के चलते खाड़ी देशों में हुए नुकसान की भरपाई की योजना बनाई जा रही है। यह खबर ऐसे समय आई है, जब ईरान ने हाल ही में कुवैत और बहरीन के खिलाफ मिसाइला और ड्रोन से हमला किया था। सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी

तेहरान गए पाकिस्तानी गृह मंत्री



इस्लामाबाद, प्रेटर: अमेरिका और ईरान के बीच फिर बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में यह दावा किया गया है कि अमेरिका-ईरान के बीच वार्ता को फिर से शुरू कराने के प्रयास में नकवी ईरान के सर्वोच्च नेता के लिए एक संदेश लेकर गए हैं।

वित्त मंत्री स्काट बेसेंट ने एक टीम को ईरान के हमलों से सहयोगी खाड़ी देशों को हुए नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ईरानी संपत्ति के उपयोग पर विचार करेगा।

राजनीतिक नेतृत्व को खुश करने के लिए काम करते हैं पुलिस अफसर : हाई कोर्ट

उप्र पुलिस के कामकाज पर सख्त टिप्पणी, कहा-अफसरों की वफादारी संविधान से नहीं, सत्ताधारी दल के प्रति

विधि संवाददाता, जागरण • प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज्य के पुलिस अफसरों की वफादारी संविधान के प्रति नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के प्रति है। फील्ड के अफसर 'ट्रांसफर-पोस्टिंग इकोनमी' ध्यान में रखकर आचरण तय करते हैं और राजनीतिक नेतृत्व को खुश करने के लिए काम करते हैं। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने इन तल्ख टिप्पणियों के साथ गाजियाबाद निवासी राजेंद्र त्यागी व दो अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई निरस्त कर दी।

पीठ ने कहा, यह कड़वा सच है कि कई सरकारों में राज्य की प्रशासनिक मशीनरी राजनीतिक घुसपैठ का शिकार रही है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन प्रतिभा के आधार पर न होकर राजनीतिक सरपरस्ती के औजार बन गए हैं। वफादार अफसरों को मलाईदार जिले इनाम में मिलते हैं, जबकि स्वतंत्रता से काम करने वाले अफसरों को महत्वहीन जगहों पर भेज दिया जाता है। कोर्ट ने लक्ष्य साध कर की गई कार्रवाई पर भी चिंता जताई। मुठभेड़, चुनिंदा क्लैकडाउन

▶ कहा-फील्ड के अफसर 'ट्रांसफर-पोस्टिंग इकोनमी' को ध्यान में रख तय करते हैं आचरण



▶ हाई कोर्ट ने गाजियाबाद के तीन याचियों के खिलाफ निरस्त की गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही

संवैधानिक शासन को व्यक्तिगत स्वार्थ या सुविधा के अधीन नहीं किया जा सकता। राज्य तंत्र को कानून और संविधान के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए, न कि किसी सत्ताधारी प्रतिष्ठान के प्रति। 'सामंती मानसिकता' वाले नेता और अफसरों ने संवैधानिक शासन को जनता की सेवा का माध्यम बनाने की बजाय निजी हुकूमत का औजार बना दिया है।

-इलाहाबाद हाई कोर्ट

कानपुर के बहुचर्चित बिकरु कांड का भी उल्लेख

कोर्ट ने अपने आदेश में कानपुर के बहुचर्चित बिकरु कांड का उल्लेख किया है। इस घटना में क्षेत्राधिकारी (सीओ) समेत आठ पुलिसकर्मी बलिदान हुए थे। पुलिस टीम गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई थी। कोर्ट ने कहा, पुरे आपरेशन की निगरानी करने वाले अधिकारी को 'फार्मल काशन' यानी औपचारिक चेतावनी भर मिली। कोर्ट ने कहा, उसे समझना मुश्किल भरा लग रहा है कि इतनी बड़ी निगरानी की चूक के बाद सजा सिर्फ औपचारिक चेतावनी कैसे हो सकती है? ऐसी "इंस्टीट्यूशनल इम्प्युनिटी" (संस्थागत जवाबदेही से मुक्ति) की संस्कृति से अफसर बेलगाम हो जाते हैं और जवाबदेह नहीं रहते।

व 'असुविधाजनक' माने जाने वाले लोगों के खिलाफ यूपी गैंगस्टर एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1986 के दुरुपयोग पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा,

'गृह सचिव को कानून-व्यवस्था में सरकार की नीतियों को निष्पक्ष रूप से लागू करने वाला संवैधानिक प्राधिकार होना चाहिए, पर व्यवहार में कुछ

अफसर इस पद पर पहुंचकर "स्वार्थी हितों के वाहक" बन जाते हैं।' पोस्टिंग की सिफारिश, विभागीय कार्रवाई की मंजूरी और कोर्ट की कार्यवाही में जवाब देते समय उनमें निष्पक्ष संवैधानिक सोच की जगह 'निजी या बाहरी' वाली बात दिखती है। कानून के शासन को असुविधा की तरह देखा जाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।

याची की तरफ से कहा गया कि गाजियाबाद कमिश्नरेट में गैंग चार्ट अनुमोदित करते समय जिलाधिकारी मीटिंग में नहीं थे। पुलिस कमिश्नर ने अकेले ही मंजूरी दे दी, जबकि नियमानुसार दोनों की संयुक्त बैठक जरूरी है। कोर्ट ने गाजियाबाद के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को भी कड़ी चेतावनी दी। उनकी ही निगरानी में गलत गैंग चार्ट अनुमोदित हुआ था। अभियोजन ने राजेंद्र त्यागी को गैंग लीडर व उसके बेटे दीपक त्यागी को सदस्य बताया। बहू ललिता के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। आरोप था कि पिता-पुत्र ने गाजियाबाद और जालौन में जमीन देने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, आपराधिक धमकी दी। इसी आधार पर दर्ज प्राथमिकी के क्रम में गैंगस्टर लगाया गया।

भारत और नेपाल संबंधों की दिशा में बदलाव लाने का अवसर : जयशंकर

नई दिल्ली, प्रे़र : भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ दो देशों की सीमाओं का मेल नहीं, बल्कि दो दिलों और साझी संस्कृति का ऐसा संगम है जो सदियों से अटूट रहा है। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ हुई 'बेहद आत्मीय बैठक' में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है जब दोनों देश अपने आपसी संबंधों को एक ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ दे सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस संकल्प को दोहराया जिसमें भारत अपने इस पड़ोसी मित्र देश के साथ मिलकर तरक्की, समृद्धि और दोनों देशों के नागरिकों के बेहतर भविष्य के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने को प्रतिबद्ध है।

पुराने भरोसे से नए युग की शुरुआत: जयशंकर ने दोनों देशों के 'रोटी-बेटी' के पारंपरिक और आत्मीय संबंधों को याद करते हुए कहा कि हमारा रिश्ता आपसी विश्वास, सद्भावना और साझी विरासत की मजबूत बुनियाद पर टिका है। व्यापार, कनेक्टिविटी और संस्कृति के

▶ बोले - समय आ गया है जब दोनों देश अपने आपसी संबंधों को एक ऐतिहासिक व निर्णायक मोड़ दे सकते हैं

नई दिल्ली में शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने की मुलाकात। प्रे़र >>



बिना किसी 'पुरानी कड़वाहट' के भविष्य की ओर कदम

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की यह तीन दिवसीय भारत यात्रा हालिया सीमा विवाद की छाया के बीच बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उन्होंने बेहद सकारात्मक और भावुक रुख अपनाते हुए कहा कि नेपाल भारत के साथ अपने संबंधों को "सर्वोच्च प्राथमिकता" देता है। उन्होंने साफ किया कि नेपाल की नई सरकार अतीत की किसी नकारात्मक विरासत या "पुरानी कड़वाहट के बोझ" को ढोने के बजाय, भारत के साथ एक बिल्कुल नए, व्यावहारिक और परिवर्तनकारी रिश्ते की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर अब दोनों देशों को स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे आधुनिक क्षेत्रों में कदम बढ़ाना चाहिए।

पश्चिम एशिया के संकट के दौर में भी भारत ने नेपाल को बिना किसी बाधा के ईंधन की आपूर्ति जारी रखकर अपनी सच्ची दोस्ती और संप्रभुता के प्रति एकजुटता को साबित किया है।

खाड़ी में घमासान : अमेरिका-ईरान ने एक दूसरे पर किए हमले

युद्धविराम पर खतरा ▶ ईरान द्वारा अमेरिका समर्थित तेल टैंकरों को वापस लौटाने पर शुरू हुआ संघर्ष

अमेरिकी नौसेना ने चार ईरानी ड्रोन मार गिराए, केश्म व सिरिक में रडार साइट नष्ट की

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

अमेरिका और ईरान के बीच लागू नाजुक युद्धविराम के बावजूद खाड़ी क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ गया है। न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सैंटकाम) ने दावा किया है कि ईरान ने शुक्रवार को होर्मुज जलडमरूमध्य तथा खाड़ी देशों की दिशा में ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिन्हें अमेरिकी व सहयोगी रक्षा प्रणालियों ने विफल कर दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका ने शनिवार को उसके निगरानी ठिकानों पर हमले किए। यहां से ईरानी सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। तेहरान ने इसे युद्धविराम उल्लंघन बताया है।

आइएनएस के अनुसार, घटनाक्रम की जानकारी देते हुए आइआरजीसी ने कहा, शुक्रवार रात डेढ़ बजे अमेरिकी नौसेना के मार्गदर्शन में होर्मुज स्ट्रेट से निकलने का प्रयास कर रहे चार तेल टैंकरों को वापस लौटने की चेतावनी दी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, ईरान समझौता क्यों नहीं कर रहा

एनआइ के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से बातचीत में कहा, ईरान के लिए समझौता करना आसान नहीं है, इसलिए देर हो रही है। ईरान के पास अब भी 21-22 प्रतिशत मिसाइल भंडार मौजूद है। ट्रंप ने कहा, ईरान के नेता बहुत मजबूत हैं और गर्व से भरे हुए हैं। ईरानियों के सामने एक ऐसी स्थिति है, जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके पास विकल्प नहीं है। उन्हें समझौता करने में थोड़ा समय लगेगा। उधर, सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने सीएनएन से कहा, ट्रंप प्रशासन यदि समझौता चाहता है तो उसे 24 अरब डालर के प्रीज ईरानी फंड को रिलीज करना होगा। कहा, अमेरिका ने दोबारा हमले किए तो वह अंधेरी गलियों में खो जाएगा।

गई। एक टैंकर को निशाना भी बनाया गया। इसके बाद टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट की ओर लौटना पड़ा। इसके बाद करीब ढाई बजे अमेरिकी ड्रोन ने केश्म द्वीप व सिरिक काउंट्री पर हमला किया।

अमेरिकी हमलों के जवाब में आइआरजीसी की एयरोस्पेस डिवीजन ने कुवैत में अमेरिकी सेना के अरली अल सलेम एयर बेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवे बेड़े को निशाना बनाते हुए सात मिसाइलें और

ड्रोन दागे। साथ ही चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसे हमले दोहराए गए तो जवाब और अधिक कठोर होगा।

सैंटकाम के अनुसार, छह मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया गया, जबकि एक मिसाइल लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गिर गई। इससे पहले अमेरिकी बलों ने होर्मुज जलडमरूमध्य की ओर बढ़ रहे ईरान के चार हमलावर ड्रोन नष्ट कर दिए थे। अमेरिकी सेना का कहना है कि ये ड्रोन क्षेत्रीय समुद्री यातायात के लिए

इजरायली हमले में लेबनान में सैन्य अफसरों समेत नौ मारे गए

एपी के अनुसार, इजरायल और हिजबुल्ला के बीच युद्धविराम के बावजूद जारी संघर्ष में शनिवार को दो लेबनानी सैन्य अधिकारी और एक सैनिक समेत नौ लोगों की मौत हो गई। हालांकि इजरायली सेना ने कहा कि वह सैन्य कार्रवाई में लोगों की मौत के मामले की जांच कर रही है। हमले में मरने वालों में लेबनान सेना के ब्रिगेडियर जनरल और कैप्टन शामिल हैं।

यहाँ लेबनान के राष्ट्रपति जोसफ औन ने इसे लेबनानी संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और घटना की निंदा की।



इजरायल द्वारा शनिवार को लेबनान पर किए गए हमले के बाद धुएं का गुबार। एएफपी

तत्काल खतरा थे। इसके बाद संभावित हमलों को रोकने के लिए गेरुक और केश्म द्वीप पर स्थित निगरानी रडार ठिकानों को निशाना बनाया। सैंटकाम ने इससे जुड़े वीडियो फुटेज भी साझा किए।

ज्ञात हो, बुधवार को कुवैत के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के निकट हुए हमले में एक नागरिक की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। हालांकि, ईरान ने इस हमले से

इन्कार किया था। युद्धविराम लागू होने के बाद किसी खाड़ी देश में यह पहला ज्ञात नागरिक हताहत माना जा रहा है।

रायटर के अनुसार, खाड़ी में गहराते तनाव के बीच पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी एक बार फिर मध्यस्थता तेज करने के लिए ईरान के दौरे पर पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि वह ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के लिए पाकिस्तान का संदेश लेकर पहुंच रहे हैं।

Not seeking mediation on border dispute: Nepal FM

Kathmandu's focus is on establishing claim on tri-junction; new 'political reality' in Nepal under PM Shah not in favour of tying relations with India to 'old baggage', says visiting Foreign Minister Khanal

Kallol Bhattacharjee
NEW DELHI

Kathmandu is focused on establishing Nepal's claim on the Kalapani-Lipulekh-Limpiyadhura tri-junction and is not "asking for mediation" by third parties, Nepal's Foreign Minister Shisir Khanal said here on Sunday.

At a press conference at the Embassy of Nepal, Mr. Khanal said he represented a "completely new political reality in Nepal" that was determined to deliver "uncompromising good governance". The new government of Prime Minister Balendra Shah was not in favour of tying Nepal-India relations down to "old baggage", he added.

"We want to solve our disputes through diplo-



Field trip: Nepal's Foreign Minister Shisir Khanal visits the Embassy of Nepal in New Delhi on Sunday. ANI

matic processes. We just want to see if we can access some of the documents that might be in libraries or museums in the U.K. Our position was not that we were asking for mediation," Mr. Khanal said, elaborating on Mr. Shah's remarks that Nepal was in contact with China and the

U.K on the Kalapani-Lipulekh-Limpiyadhura dispute with India.

Shah's statement

"The problems that existed when British India left the region still persist, so we believe Britain also has a role to play in this matter," Mr. Shah had said in Ne-

pal's Parliament, stirring debates.

India's Ministry of External Affairs had issued a rebuttal, reiterating that India and Nepal had established a bilateral mechanism for discussing the dispute, and there was no scope for third-party intervention.

As a new-generation political entity, the Rastriya Swatantra Party refuses to "look at India through the distorted, hypersensitive lens of 20th century geopolitics", Mr. Khanal said. "Instead, the RSP wants to shift the entire vocabulary of Nepal-India relations away from geopolitical friction and square it firmly on development diplomacy," he added.

CONTINUED ON

» PAGE 12

Protest will continue until Pradhan quits: CJP founder

Snehal Mutha

MUMBAI

A day after organising a demonstration in New Delhi demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, the founder of the online movement Cockroach Janta Party (CJP), Abhijeet Dipke, on Sunday said the protest would continue.

Hundreds of people, including students, had gathered at the Jantar Mantar on Saturday demanding the resignation of the Minister over the alleged irregularities in CBSE examinations, entrance tests for higher education, and recruitment examinations. Climate activist Sonam Wangchuk and CPI(ML) Liberation general secretary Dipankar Bhattacharya also came in support of the CJP's demands.

Addressing presspersons at his hometown in Chhatrapati Sambhajinagar district in Maharashtra on Sunday, Mr. Dipke said,



The youngsters of the country are not scared of the government. We will continue to fight for him [Union Education Minister Dharmendra Pradhan] to resign. Someone must be held accountable

ABHIJEET DIPKE
CJP founder



"What to do with this government? No employment, no proper exams. The youngsters of the country are not scared of the government. We will continue to fight until he [Mr. Pradhan] resigns. Someone must be held accountable."

He said the protest was a success, saying that around 7,000 people took part in it, and dismissed claims that people were paid to take part in the demonstration. "I came to the venue direct from the airport [after arriving from the U.S.]. How could I have paid them? The BJP is also

running a fake campaign that not many people turned up at the venue."

"I informed my friends that I am going to India and very much mentally prepared to go to jail also. Someone must raise the voice. In our country, the politics has been limited to elections. Once elections are done, [people] forget about it for the next five years," Mr. Dipke said.

On the future course of action, Mr. Dipke said, "We will discuss with the members of the community, take their suggestions, and accordingly decide on our next move."

From borderland to India's strategic resource frontier

Within days of one another, official platforms of the Ministry of Mines cast several northeastern States in a similar frame – as repositories of strategic minerals and untapped potential. Manipur was described as a “quiet mineral frontier”, Arunachal Pradesh as a “resource-rich frontier”, while Meghalaya and Mizoram were portrayed through comparable narratives that emphasised the hidden wealth beneath their hills. Governments routinely publicise natural resources and development opportunities, and such descriptions would ordinarily attract little attention.

Taken together, however, they point to a broader shift in the language through which the northeast is increasingly being framed in the national conversation and strategic picture.

The critical mineral push

The timing is significant because critical minerals have moved from geological discussions into strategic ones. Lithium, cobalt, graphite, nickel and rare earth elements increasingly shape industrial competition, technological manufacturing and energy transitions. Batteries, semiconductors, renewable technologies and defence systems depend upon them, and countries have begun repositioning themselves around access to these resources. India itself continues to depend on imports for several critical minerals and has consequently expanded exploration efforts. According to a Ministry of Mines reply in Parliament, the Geological Survey of India undertook 43 critical mineral exploration projects across northeastern States during the 2022-23, 2023-24 and 2024-25 field seasons, covering minerals such as graphite, vanadium, lithium, rare earth elements, nickel and cobalt. Exploration activity has expanded across Arunachal Pradesh, Meghalaya, Assam, Nagaland and Manipur. In Manipur, projects involving nickel, cobalt and chromium exploration have recently been initiated.

Geological surveys have pointed toward mineral potential across the region for years.



**Sangmuan
Hangsing**

Researcher and
alumnus of the
Kautilya School
of Public Policy

Critical mineral
ambitions must
account for the
people, land and
history of
northeast India

What appears to be changing is the language through which that significance is increasingly being understood. The northeast has long held strategic significance that extends beyond geology, but the framework through which that significance is understood now appears to be widening.

Shift in language

For decades, the northeast has figured in national strategy largely through the language of borders and security. Discussions have centred on insurgencies, territorial management, connectivity initiatives and geopolitics considerations involving neighbouring countries, while infrastructure and development were often justified as instruments of strategic access and territorial security.

The language of resources is increasingly entering a strategic space once dominated by concerns over borders and security. Critical minerals are now discussed alongside trade corridors and geopolitical access, with territorial and resource security converging. Places once viewed mainly as sensitive border regions are increasingly seen as strategic assets.

The repeated use of the word frontier is revealing, because frontiers rarely function as neutral descriptions. They do not merely describe geography; they often reflect how States imagine it. Historically, frontiers have been viewed as spaces awaiting integration, development or extraction because they appear as landscapes of future possibility.

The difficulty is that frontiers are rarely empty spaces waiting to be discovered. The hills and valleys of the northeast already contain dense social and political worlds structured around customary land systems, local institutions and long-standing relationships with territory. Questions of land often extend beyond economics, as they are also tied to authority, identity and memory. Resource extraction thus enters landscapes that already possess institutions and histories of their own.

These questions become particularly significant in regions where political uncertainties continue to shape everyday life. In Manipur, years of violence and displacement have intensified debates over land and territorial arrangements. Similar concerns about ownership, ecological vulnerability and local participation have surfaced across the northeast at different times. Projects involving land often acquire meanings that extend beyond development, as communities interpret them through the lens of trust, representation and political inclusion.

Resources and inclusion

India's search for critical resources is understandable within a global environment increasingly shaped by supply-chain uncertainty and strategic competition. The northeast itself also requires infrastructure, employment and economic opportunities that have remained uneven for decades. Questions surrounding resource development rarely fit neatly into positions of support or opposition.

How quickly these transitions unfold and who shapes them may matter as much as the resources themselves. For a very long time, national priorities and local realities in the northeast often moved at different speeds. Connectivity projects sometimes arrived without corresponding economic ecosystems, while strategic considerations frequently overshadowed questions surrounding participation and representation. Resource development risks reproducing similar tensions if extraction begins moving faster than institutions capable of managing its social consequences.

What is being debated extends beyond the minerals beneath the hills. The northeast has spent years being viewed first as a border to be secured and then as a corridor to be connected. If it now begins entering national imagination as a landscape of strategic resources, the question is whether this new frontier will finally include the people who already inhabit it, or merely assign another purpose to the land beneath their feet.

The Ordinance question before the SC

The Collegium's acceptance of an Ordinance that creates four additional judges' posts raises questions about judicial independence, security of tenure and the appearance of detachment from the executive; court has taken a calculated risk by staking its independence on the goodwill of the government and Parliament

LETTER & SPIRIT

V. Venkatesan

In February 1937, the President of the United States of America, Franklin D. Roosevelt, asked Congress to enlarge the nine-judge Supreme Court. He sought a new justice for each one past 70 who refused to retire, up to 15 in all. The Senate Judiciary Committee saw through it. It preferred "an independent Court, a fearless Court," to one that bent "out of fear or sense of obligation to the appointing power." The Senate refused, with 70 members voting against and 20 in favour, and the plan was dead.

In Delhi last week, five judges took the oath; three occupy chairs, that no statute has created. They sit because the President, by Ordinance, lifted the sanctioned strength from 34 to 38.

Ordinance-made seats

The five are fit for office: four sat as Chief Justices of High Courts, the fifth came from the bar. Their elevation is not the grievance; the manner of it is. The Ordinance was promulgated on May 16, when the Court sat at 32 against a sanctioned 34. Two lawful vacancies existed; two of Tuesday's appointments filled them. The other three rest on the Ordinance alone.

Article 124(i) leaves the number of judges to what Parliament may prescribe. An Article 123 Ordinance carries, for its life, the force of an Act. Independence of the judiciary is a basic feature of the Constitution. It is also about whether the court holds its seats free of obligation to the political branch. A court that owes three chairs to a six-week renewable Ordinance holds them at the executive's sufferance.

A test of principle

In 2015, a Constitution Bench decided *Supreme Court Advocates-on-Record Association vs Union of India*. It struck down the 99th Amendment and the National Judicial Appointments Commission. Parliament had passed it 367 to nil in the Lok Sabha, with the States ratifying. The commission was to have six members: the Chief Justice, the two senior-most judges after him, the Union Law Minister, and two eminent persons. The eminent persons were to be chosen by a panel of the Prime Minister, the Chief Justice, and the Leader of the Opposition. That composition was meant to keep the choice neutral. Yet the Act provided that any two members could veto a name. The court feared that the Law Minister and even one eminent person could thus block a candidate the judges favoured. It held that this destroyed the judiciary's primacy in its own appointments.

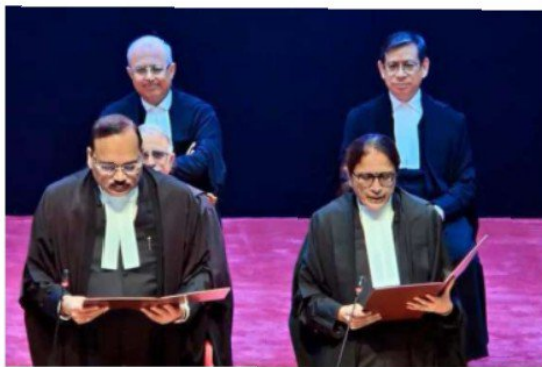
Yet the Supreme Court Collegium has accepted an Ordinance that seats three of its own, despite the uncertainty over its fate. Under Article 123, the President may withdraw an Ordinance at any time. Both Houses may disapprove it by resolution. Otherwise, it ceases to operate six weeks after Parliament reassembles.

The court itself taught the country to distrust the Ordinance. In *D.C. Wadhwa vs State of Bihar* (1986), it called governance by re-promulgated ordinance a fraud on the Constitution. In *Krishna Kumar Singh vs State of Bihar* (2017), a seven-judge Bench ruled against using ordinance-making power as a parallel source of legislation.

If the Bill replaces the Ordinance, the



GETTY IMAGES



CJI Surya Kant administers the oath of office to Justice V. Mohana as a judge of the Supreme Court, in New Delhi on June 2. She is only the second woman to be elevated directly from the Bar to the court. PTI

anomaly closes. If not, the apex court's strength reverts to 34, and the executive cannot bridge the gap by re-promulgation, the fraud *Wadhwa* condemned. Whether a judge appointed to an Ordinance-created post can be removed once that post lapses is untested. Their judgments hold under the *de facto* doctrine, affirmed in *Gokaraju Rangaraju vs State of Andhra Pradesh* (1981). The subtler harm is to appearance: in any matter touching the Union, the government whose majority must regularise their seats may appear before them. A judge whose tenure lies, even loosely, in one party's gift cannot wear the detachment the office demands.

The calculated risk

The court sits at 37; the 38th and last sanctioned post is empty, the calendar suggests why. Justice Pankaj Mishra retires on June 16 and Justice J.K. Maheshwari on June 28. Their retirements reopen two lawful seats, into which two of the three Ordinance judges move. A judge in the 38th post would be the junior-most. Its occupant would reach a lawful seat only at Justice Satish Chandra Sharma's retirement on November 29, months after the Ordinance expires. Leaving it empty spares the court a judge stranded that long.

That leaves Justice V. Mohana, alone of the five from the bar and so junior-most,

The five are fit for office: four sat as Chief Justices of High Courts, the fifth came from the bar

on an Ordinance post. She can reach a lawful seat only when Justice Sanjay Karol retires on August 22. Here, the Collegium seems to have taken a calculated risk. Justice Karol's retirement all but coincides with the Ordinance's likely lapse, six weeks into the monsoon session. The replacing law should thus arrive first, and even a short delay is caught by his vacancy, which absorbs her. Her position turns precarious only if the Ordinance is rejected or lapses before August 22. Then the strength reverts to 34, the court still sits at 35, and she holds a post that the law no longer recognises. That a judge of the highest court should depend on which reading prevails, and on when Parliament meets, is the disquiet.

Larger question

The wager will likely be won; the government has the numbers, and the Opposition will not unsettle freshly sworn judges. But that is not the point. The court has staked its independence and its judges' security of tenure on the goodwill of the executive and Parliament.

The U.S. Senate's warning of 1937 was against a court bound by obligation to the appointing power. The graver danger is a court that no longer notices the obligation. Independence of the judiciary is not only the right to say no to the executive. It is the instinct to want to. (V. Venkatesan is Contributing Editor at *Supreme Court Observer*. Views expressed are personal)

THE GIST

Five judges were sworn in to the Supreme Court after the sanctioned strength was raised from 34 to 38 through a Presidential Ordinance; while two appointments filled existing vacancies, three were made to newly created posts.

The Supreme Court has previously held in cases such as *D.C. Wadhwa vs State of Bihar* and *Krishna Kumar Singh vs State of Bihar* that ordinance-making power cannot become a parallel source of legislation and that repeated promulgation of ordinances is unconstitutional.

If Parliament does not replace the Ordinance with a law, the court's sanctioned strength would revert to 34, raising unresolved questions about the status of judges appointed to Ordinance-created posts and the legal implications of such appointments.

Russian oil imports, prices jump; U.S. share goes down

While Russia's share in India's oil imports stood at 34% in terms of volume in April 2026, India's dependence on oil from the U.S. fell to 8-month low, accounting for just 3.8% in terms of volume

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

Russia's share in the value of India's oil imports jumped back up to an 11-month high of nearly 38% in April 2026 as India continued to increase its dependence on it against the backdrop of the ongoing West Asia crisis.

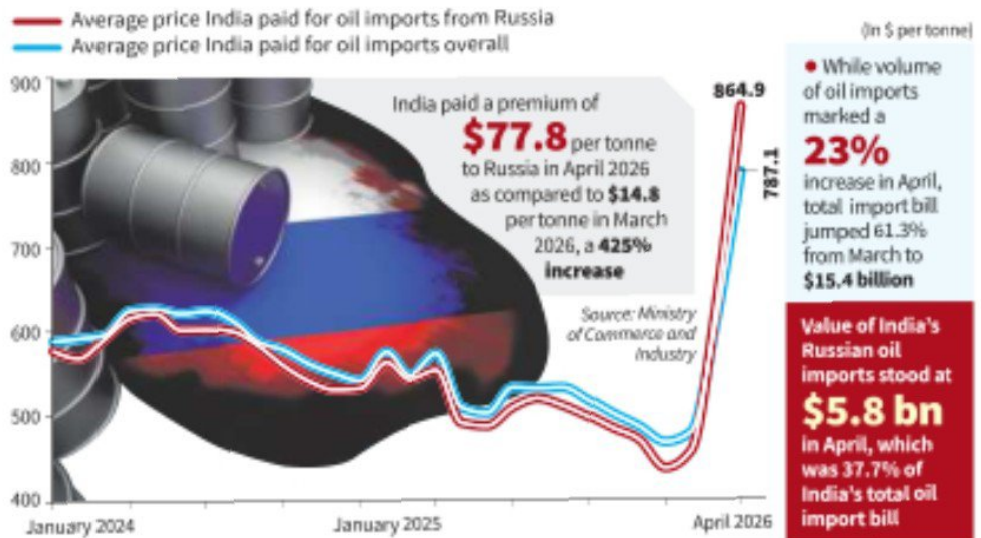
This increasing dependence was accompanied by a 425% jump in the premium being charged by Russia for its oil, in contrast to the discount it had been offering until recently.

Russia's share in India's crude imports in April stood at about 34% in terms of the volume. At the same time, India's dependence on oil from the U.S. fell to multi-month lows in terms of both value and volume.

Oil imports back up

An analysis of data from the Ministry of Commerce and Industry shows that India's total oil imports bounced back to 195.3 lakh tonnes in April after having dipped in March to 158.5 lakh tonnes following the start of the West Asian crisis.

Premium pricing | India's increasing dependence on Russian oil has been accompanied by a higher premium it is paying



However, while this worked out to a 23% increase over March in terms of volume, the surging price of oil meant that India's total oil import bill jumped 61.3% to \$15.4 billion in April, as compared to its level in the previous month.

Within this, the volume of India's oil imports from Russia stood at nearly 67 lakh tonnes in April, up 27% from March and making up 34.3% of the total amount of oil India imported during the month.

The rise in prices had a

significant impact on the amount India paid for this oil.

The Hindu had reported last month that the discount Russia used to offer India for its oil had turned into a premium in March.

Higher premium

The data now shows that India paid an even higher premium for Russian oil in April than it did in March.

The total value of India's Russian oil imports stood at \$5.8 billion in April 2026, which was 37.7% of India's total oil import bill

that month.

In April, India paid Russia \$864.9 per tonne for its oil, while it paid \$787.1 per tonne overall for its oil imports from all countries. This works out to a premium of \$77.8 per tonne as compared to a premium of \$14.8 per tonne paid to Russia in March 2026, a 425% increase.

On the other hand, the U.S. accounted for just 2.9% of India's oil bill in April, an eight-month low. In terms of volume, it accounted for 3.8%, also an eight-month low.

Hundreds gather at CJP protest seeking Pradhan's resignation



Screen to street: CJP founder Abhijeet Dipke and Ladakh activist Sonam Wangchuk with supporters of the outfit during the protest at Jantar Mantra in New Delhi on Saturday. SHASHI SHEKHAR KASHYAP

Aroon Deep
NEW DELHI

The first in-person protest of the online movement Cockroach Janta Party (CJP), demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, attracted a crowd of over 1,500 people at Jantar Mantra here on Saturday.

Ladakh activist Sonam Wangchuk joined the demonstration led by CJP founder Abhijeet Dipke, where protesters raised slogans against the Union government and sought accountability, amid the cancellation of the National Eligibility-cum-Entrance Test-Undergraduate (NEET-UG) and the issues with the Central Board of Secondary Education

(CBSE) Class 12 board examinations.

Hundreds gathered in the first hour of the protest and many were seen wearing cockroach masks, which were being distributed at the venue. The crowd comprised a large number of youngsters.

Six detained

While no untoward incidents were reported, some counter-protesters raised slogans near the protest site and the Delhi Police detained six people to prevent a possible confrontation. The detentions were made as a precautionary measure to maintain law and order after receiving inputs about the possibility of tensions between supporters and opposers of the movement, the police

said. Earlier, Mr. Dipke, who landed in New Delhi after a day-long journey from Boston in the U.S., told presspersons gathered at the airport that "the Education Minister has to resign". "Five students have committed suicide," he added. At the Jantar Mantra, he led chants seeking Mr. Pradhan's resignation.

"We are not here to protest but to appeal that government should be accountable," Mr. Wangchuk, who spent nearly six months incarcerated under the National Security Act till March, said after joining the protest.

CONTINUED ON

» PAGE 8

STUDENTS JOIN PROTEST

» PAGE 9

Scientists rule out worst-case climate scenario, with caution

The doomsday climate scenario is now unrealistic due to slower emissions growth; however, the decline is still not nearly enough to limit global warming to the most optimistic scenario

Neelima Vallangi

Climate scientists have released a new set of global emission scenarios that will serve as the basis for climate research over the coming years. And here, the worst-case scenario that put the world on track to experience warming well above 4° C by the end of the century has finally been retired.

Called RCP8.5, the high-emission scenario was deemed implausible in the latest revision thanks to the rapid adoption of renewable energy and countries implementing climate policies.

Scientists say climate action eliminating the 'doomsday scenario' is encouraging because that means the extreme consequences associated with 4° to 5° C of warming can now be avoided.

However, they warned, the planet is still on track to experience drastic climate change under current policies.

After months of experiments and collaboration across dozens of research centres worldwide, a team of earth system modelling experts published seven new emissions scenarios in April. In this set, the new highest emission scenario projects an overall warming of around 3.5° C by 2100.

RCP8.5 is out "mainly because of the rapid transition to renewable energy in several countries around the globe, particularly China, which is number one in terms of carbon

Not business as usual

The new highest emission scenario projects an overall warming of around 3.5° C by 2100

- Scientists have retired the extreme RCP8.5 climate scenario because global warming above 4° C now seems implausible

- The revision comes thanks to countries adopting renewable sources of energy and implementing climate policies

- Even so, current global policies place the world on a 'medium pathway' towards roughly 2.8° C of warming by 2100

- Keeping global surface temperature rise below 1.5° C also appears impossible without a significant period of temporary overshoot

- Even a moderate global warming level of 2° C still poses severe risks for extreme weather and global food security

- New research integrates updated data to refine climate models while accounting for remaining uncertainties about planetary sensitivity



Making a difference: 'Emissions have peaked and are declining in the U.S. and Europe, and are plateauing in China'. RABH SHASHA

emissions today," Govindaswamy Bala, professor at the Center for Atmospheric and Oceanic Sciences, Indian Institute of Science, who was also part of the latest scenario development, said. "Emissions have peaked and are declining in the U.S. and Europe, and are plateauing in China."

At the same time, there remains no plausible path to keep warming below 1.5° C without significant overshoot under the current emissions trajectory. Overshoot means temporarily exceeding the 1.5° C of warming threshold before returning to the limit by 2100.

"While that original high emissions path has become irrelevant, getting to the low emission levels consistent with preventing dangerous climate change has also become much

more difficult to achieve," Detlef van Vuuren, a climate scientist at the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency who has led emissions scenario development for many years, said.

In 2011, when RCP8.5 emerged as one of the four 'Representative Concentration Pathways' scientists introduced, its drastic prognoses for the world took on a life of their own. For scenario developers, it denoted the world in which governments enacted no climate policy; but many climate modellers used RCP8.5 as the "business as usual" scenario. However, scientists had intended it only as an edge case: to model earth systems under unabated fossil fuel expansion and high population growth.

In 2016, scientists upgraded the RCPs to SSPs, or

'Shared Socioeconomic Pathways', which integrated factors such as economic growth and population expansion alongside greenhouse gas concentrations. RCP8.5 then became SSP5-8.5, with a projected warming of 4.4° C by 2100.

Many scientists said the new revision demonstrates the usual process of doing climate research: by constantly integrating new information and eliminating unrealistic scenarios.

That said, the world has not averted the worst of climate change. A recent study in *Nature* reported that even moderate global warming of 2° C will increase the risk of extreme outcomes such as droughts in key breadbasket regions, extreme rainfall over highly populated areas, and fire weather extremes across forests. The world is close to the medium path-

way in the new CMIP7 scenarios: facing an expected warming of up to 2.8° C by 2100.

"The new scenarios can shed light on what to expect but do not radically change the fact that India is highly exposed to extreme events, in all scenarios, because they take us into dangerous 2° C and beyond-2° C territory," Chandni Singh, climate adaptation researcher at the Indian Institute for Human Settlements and an IPCC Lead Author, said.

RCP8.5 assumed that the concentration of carbon dioxide in the atmosphere would triple (to 850-900 ppm) due to increasing coal use and that the world's population would swell beyond 10 billion. Both these possibilities have since become unrealistic.

That said, "if the climate turns out to be much more sensitive [to CO₂ concentration], then we could end up with warming levels associated with RCP8.5," Dr. van Vuuren said. "Secondly, it is still possible to hit those warming levels if we are on the high emission pathway, but around the year 2150."

There is already some evidence that we may have underestimated climate sensitivity, as scientists have been baffled by accelerating global warming in the last three years. They hope to resolve this uncertainty as climate models simulate earth systems in these new scenarios with new data.

Neelima Vallangi is an independent climate journalist